

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 50

संख्या: 224

प्रभात

कोटा, गुरुवार 29 मई, 2025

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बड़े जोश से 2025 को पार्टी का “ऑर्गनाइज़ेशन इयर” घोषित किया था

... पर छः माह बीत गए हैं, लगभग सभी राज्यों में पार्टी संगठन लगभग नदारद हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नईदिल्ली, 28 मई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े जोर-शोर से 2025 को पार्टी में “संगठन का वर्ष” घोषित किया था। लेकिन आधा साल बीत चुका है और संगठनात्मक गतिविधियों में न तो कोई विशेष हलचल दिखती है, न ही कोई ठोस प्रगति।

राज्य-दर- राज्य कांग्रेस का संगठन निष्क्रिय अवस्था में बना हुआ है। इस स्थिति के लिए कई बरिष्ठ नेता पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वेणुगोपाल उड़ाईसीसी महासचिव एव संगठन-प्रभारी हैं, लेकिन ज़मीन पर संगठन को मज़बूत करने के बजाय उनका पूरा ध्यान गांधी परिवार, खासतौर पर राहुल गांधी के साथ यात्रा करने पर रहता है और जहां भी राहुल जाते हैं, वे उनके साथ होते हैं।

वेणुगोपाल ने खुद को राहुल गांधी का मुख्य सहायक बना लिया है।

क्या यह कोई असुरक्षा की भावना है, जो उन्हें राहुल गांधी के इर्द-गिर्द बने

■ कहने को के.सी. वेणुगोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, पर, वे पूरा समय राहुल गांधी के पीछे रहते हैं। जहाँ राहुल जाते हैं, वहाँ के.सी. वेणुगोपाल भी होते हैं। असल में वेणुगोपाल चाहते हैं कि राहुल गांधी पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहे, राहुल गांधी उन्हीं की बाँत सुर्नें।

■ मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार रिक्त पद भरने का प्रयास कर चुके हैं, पर, खड़गे की लिस्ट को वेणुगोपाल हमेशा ठुकरा देते हैं।

■ पार्टी संगठन की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं है, इस समय वेणुगोपाल व उनके समर्थकों का सारा फोकस शशि थरूर को पार्टी से निकलवाने पर है और इसके लिए रोज़ नई-नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं।

■ वेणुगोपाल केरल का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं और उन्हें इसमें शशि थरूर ही बाधा नज़र आते हैं, इसलिए वे थरूर को रास्ते से हटाने में जुटे हैं और इस काम में उन्हें जयराम रमेश जैसे उन नेताओं की सहायता मिल रही है, जिनकी कुर्सी खतरे में है।

रहने के लिए प्रेरित करती है? कहना मुश्किल है। वे ऐसे एकमात्र संगठन-प्रभारी महासचिव हैं, जो हमेशा गांधी परिवार के

साथ यात्रा करते रहते हैं, जबकि यह न तो उनके पद की भूमिका है, न ही उनकी जिम्मेदारी।

इस रवैये का नतीजा यह हुआ है कि पार्टी का संगठन बुरी तरह उपेक्षित हो चुका है। एक के बाद एक राज्य में संगठनात्मक इकाइयों निष्क्रिय होती जा रही हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यों में खाली पड़े पदों को भरने की कई बार कोशिश की, लेकिन वेणुगोपाल ने इन प्रयासों को बार-बार विफल कर दिया। यहां तक कि वे खड़गे द्वारा तैयार की गई सूची तक को खारिज कर देते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि वेणुगोपाल का अधिकतर ध्यान केरल पर केंद्रित है, जहां वे खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं और वहाँ के अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने में लगे हैं।

उनका मुख्य निशाना शशि थरूर है। बताया जा रहा है कि वेणुगोपाल, जयराम रमेश और अन्य लोगों की मदद से, थरूर के खिलाफ मीडिया में नकारात्मक खबरें गढ़ रहे हैं, जबकि थरूर को दुनिया भर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर में आज कोरोना के 5 नये केस आये

जयपुर, 28 मई । राजस्थान में कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक देता नज़र आ रहा है। बुधवार को प्रदेश भर से कोविड के 7 नए मामले सामने आए, जिनमें से सर्वाधिक 5 केस जयपुर से रिपोर्ट हुए हैं। अन्य दो मामले जोधपुर से मिले हैं।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को संक्रमितों में 16 वर्षीय बालक बालोतरा से, बीकानेर से 31 वर्षीय महिला और दौसा से एक 5 वर्षीय बच्चा है। शेष चार

■ आज रिपोर्ट हुए संक्रमितों में दौसा का एक 5 वर्षीय बच्चा भी है।

मरीजों में से 51 वर्षीय, 38 वर्षीय और 40 वर्षीय पुरुष तथा 24 वर्षीय महिला जयपुर से संक्रमित पाए गए। ये केस राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठित अस्पतालों, एम्स जोधपुर (2), एसएमएस जयपुर (2), आरयूएचएस (1), जयपुरिया (1) और एक विश्वसनीय स्रोत से रिपोर्ट हुए हैं।

राज्य में वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक कुल 39 कोरोना संक्रमित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डूंगरपुर में लैपर्ड ने 4 युवकों पर हमला किया

डूंगरपुर, 28 मई (निसं)। वरदा थाना क्षेत्र के वलोता फला लिमडी गांव में झाड़ियों में छिपकर बैठे लैपर्ड ने चार युवकों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। युवकों के चिल्लाने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो लैपर्ड भाग गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वलोता फला लिमडी गांव निवासी मुकेश पुत्र मोगजी रोट, हाजा पुत्र कन्हैयालाल, लक्ष्मण पुत्र जीवा और शंकर पुत्र लक्ष्मण लाल चारों युवक लक्ष्मण की बहन रानी, पुत्री जीवा रोट की सगाई में गए थे। चारों युवक रीना की ससुराल से पैदल घर लौट रहे थे।

■ युवकों के चिल्लाने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण आ गये और लैपर्ड भाग गया।

रास्ते में वलोता डैम के पास झाड़ियों में छिपकर बैठे लैपर्ड ने मुकेश पर हमला कर दिया। उसे बचाने आए अन्य युवकों पर भी लैपर्ड ने हमला कर उन्हें घायल गंभीर रूप से कर दिया। युवकों के चिल्लाने का शोर सुनकर आस पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लैपर्ड भाग गया। सूचना मिलने पर, वरदा पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा चारों घायल युवकों को 108 एम्बुलेंस की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लैपर्ड के मुव्मत के लेकर वन विभाग को सूचना दी गई है, जिस पर वन विभाग लैपर्ड मुव्मत को ट्रैक कर रैस्क्यू करने में जुटा है।

अल्पसंख्यकों और राष्ट्रवादी समूहों, दोनों को साधने में जुटी हैं ममता बनर्जी

प.बंगाल की मु.मंत्री, देश के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती हैं

- ममता के भतीजे अभिषेक, जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान गए हैं, ने पाकिस्तान को “पागल कुत्ते का हँडलर” करार दिया। उनकी इस टिप्पणी को ममता बनर्जी की राष्ट्रवादियों का समर्थन जुटाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
- अभिषेक बनर्जी की इस टिप्पणी से राष्ट्रवादी स्रोत वाले लोग तो खुश हैं पर संभावना है कि बंगाल का अल्पसंख्यक वोट बैंक इससे नाखुश हो सकता है।
- बंगाल के राष्ट्रवादी तबके को खुश करने के लिए अभिषेक बनर्जी ने जापान में रासबिहारी बोस का भी जिक्र किया और वे उनके स्मारक पर भी गए।

कुत्ता” कहना बंगाल की मुस्लिम आबादी के बीच खतरा पैदा कर सकता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों और आतंक की हमलों के बावजूद, बंगाल का मुस्लिम समुदाय किसी भी टकराव की स्थिति में पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखता है।

मुस्लिम बिरादरी किन्हीं भी राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानती है। यहां तक कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है, तब भी बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के बयान, राष्ट्रीय या

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भले ही उन्हें प्रशंसा दिलाएं, परंतु, राज्य में अल्पसंख्यकों के बीच इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनी संयुक्त संसदीय टीम में बनर्जी की भूमिका भी कुछ हद तक जटिल रही। सरकार की ओर से टीम के लिए पहले सुझाए गए नाम को तृणमूल कांग्रेस ने खारिज कर दिया। पार्टी ने वरिष्ठ सांसद सुदीप बंधोपाध्याय को टीम के साथ जापान यात्रा पर जाने से रोक दिया और कहा कि पार्टी खुद तय करेगी कि कौन जाएगा।

बाद में पार्टी ने यूसुफ पठान के नाम को भी अस्वीकार कर दिया, जिससे उन्हें टीम से हटना पड़ा। इसके बाद ही, पार्टी ने अभिषेक बनर्जी को शशि थरुर के नेतृत्व वाली संयुक्त संसदीय टीम में बतौर प्रतिनिधि भेजा, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं।

जापान में, पाकिस्तान के खिलाफ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बारिश

नयी दिल्ली, 28 मई। देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को मानसून समय से 12 दिन पहले छत्तीसगढ़ और 13 दिन पहले ओडिशा पहुंचा। दोनों राज्यों के कुछ जिलों में तेज बारिश हुई।

महाराष्ट्र के मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ में आज भारी बारिश हो रही है। यहां बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बदलापुर, उल्हासनगर,

■ राजस्थान के अन्य भागों में लू और आंधी का प्रकोप देखा जा रहा है।

कल्याण, डोंबिवली और ठाणे के अलग-अलग इलाकों में जलभराव हो गया है।

राजस्थान में मौसम तीन रूप देखने को मिल रहे हैं। बूंदी जिले में तेज गर्मी पड़ रही है। यहां के गांव में एक बुढ़ा महिला की मौत हुई। जांच में हीटवेव से मौत की बात सामने आई। उदयपुर, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK

विचार बिन्दु

फल की इच्छा छोड़कर निरंतर कतव्य करो। जो फल की अभिलाषा छोड़कर कतव्य करते हैं, उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। –गीता

मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे किए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यकाल के ग्यारह वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिनकी देश और दुनिया में काफी चर्चा हुई। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। ग्यारह साल बाद भी मोदी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार शासन करने वाले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक 25 साल का बेमिसाल सफर पूरा करने वाली यह शख्सियत नरेन्द्र दामोदर दास मोदी आज ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पहचान कायम करने में सफल हुए हैं। मोदी में गजब का आत्मविश्वास है। प्रखर और कुशल वक्ता के रूप में उनकी राष्ट्रीय पहचान है।

मोदी की कार्यशैली, सोच, साहस, हौसला, कार्य निष्ठा, देश के प्रति समर्पण, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, नेतुत्व और कुछ कर गुजरने की ललक ने उनकी लोकप्रियता को देश ही नहीं अपितु दुनिया में भी बढ़ाने का काम किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की इन 11 सालों की उपलब्धियां बेमिसाल रही है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार के कार्यकाल में विपरीत स्थितियों के बावजूद भारत ने विश्व आर्थिक क्रांति का उद्घोष कर विकास के प्रेरक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित किया है। इस अवधि में देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सबसे अधिक सार्वजनिक निवेश हुआ है। परिणाम स्वरुप अनेक क्षेत्रों में आशातीत प्रगति कर भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। मोदी ने कश्मीर में एक ध्वज, एक निशान और एक संविधान का जनसंघ के पितृ पुरुष का सपना साकार किया। मोदी ने अनेक ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम देकर ‘मोदी है तो मुमकिन है’ की अपनी छवि बनाई।

मोदी संघ के एक विनम्र स्वयं सेवक की तरह देश की नब्ज को पहचानने में सफल हुए। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि सरकार के किसी मंत्री पर कोई भी भ्रष्टाचार या घोटाले का आरोप नहीं लगा।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जनता की आशाओं अपेक्षाओं पर नितांत खरे उतरे। जन विश्वास अर्जित कर मोदी ने देशवासियों का आत्मसम्मान व राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। देश की सबसे बड़ी वैश्विक उपलब्धियों में एक चौथी अर्थव्यवस्था बनने की है।

भारत ने जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हासिल की है। यह उपलब्धि भारत की वैश्विक भूमिका और आर्थिक नीतियों की सफलता को दर्शाती है। जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जीएसटी, आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, नारी शक्ति और कानून, तीन तलाक कानून, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और कौशल विकास,महिलाओं के लिए सैन्य सेवा में प्रवेश और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित 80 करोड़ गरीबों को रोजी-रोटी की सुविधा उपलब्ध कराकर मोदी सरकार की ग्यारह सालों की प्रमुख उपलब्धियां है। हाल ही ऑपरेशन सिन्दूर के माध्यम से पाकिस्तान में चल रहे आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति बेहद नाराजगी का भाव है। इसके बावजूद लोगों का मानना है भ्रष्टाचार को काबू करने का मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया है जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ जरूरतमंद गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचा है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सफलता के परचम फहराए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवधि में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। इस अवधि में बढती कीमती (खासतौर पर पेट्रोल-डीजल), किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी आदि की नाराजगी के बावजूद लोगों पर अभी भी मोदी का जादू बरकरार है।

महाराणा प्रतापः स्वधर्म एवं स्वदेश के लिए आजीवन संघर्षरत सेनानी



राजेश्वर सिंह

भारतीय संस्कृति व परम्परा में धर्म को मनुष्य के सहज कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है और धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय, स्वच्छता, इन्द्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध इसके दस लक्षण बताये गये हैं। भारत में सभ्यता के आदिकाल से ही मनुष्य का व्यक्तितगत व सामाजिक जीवन उपर्युक्त महान मानवीय मूल्यों पर आधारित दस लक्षण धर्म के मूलाधार पर प्रतिष्ठित था। भारतीय भूभाग के विपुल विस्तार व आवागमन के त्वरित साधनों के अभाव की वजह से यह एकान्त सांस्कृतिक क्षेत्र विभिन्न राज्यों अथवा राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था किन्तु वहाँ भी वैश्वगत जीवन, सामाजिक व्यवस्था व राज व्यवस्था का आधार दस लक्षण धर्म ही था।

विदेशी आक्रान्ताओं के भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य न केवल इस विस्तृत भूभाग की विपुल धन सम्पदा

का दोहन था वरन् अपना राज्य स्थापित कर यहाँ के धर्म, संस्कृति, परम्परा व आधारभूत जीवन मूल्यों को ध्वस्त कर जनसामान्य में दास मनोवृत्ति को अधिरोपित करना था ताकि उनका आधिपत्य निष्कट हो सके। आक्रान्ता व उनके वंशज इस उद्देश्य की प्राप्ति में आंशिक रूप से सफल अवश्य हुए क्योंकि भारतीय समाज में गुण –कर्म आधारित गतिशील वर्ण व्यवस्था कालक्रम में वंशानुगत अपरिवर्तनीय जाति व्यवस्था में तब्दील हो चुकी थी और अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का अंग बन चुका था, जिससे पंडित एक छोटे से वर्ग ने लाभ, लोभ या आतंक की वजह से धर्म परिवर्तन अवश्य किया किन्तु व्यापक जन समुदाय की धर्मनिष्ठा अटूट और अपरिवर्तनीय ही रही। इसके मद्देनजर विदेशी मूल के शासक ने अपनी रणनीति में बदलाव किया व स्थानीय शासकों के साथ सहअस्तित्व, सहयोग व समायोजन की नीति का अवलम्बन किया। यह नीति ऊपर से तो अत्यन्त सहिष्णु, समावेशी व उदारवादी प्रतीत होती थी किन्तु अन्दर से आक्रांताओं के मूलभूत उद्देश्य अपरिवर्तनीय ही रहे।

राजपुताना के राज्यों में केवल मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने मुगल साम्राज्य का अंग बनने से स्पष्ट रूप से इंकार किया जिसका खामियाजा वहाँ के शासकों व जन साधारण को भुगतान पड़ा। 1567 ई. में अकबर ने जब चित्तौड़ पर चढाई की ,उस समय

अपने सरदारों एवं सेनानायकों की सलाह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ का गढ छोड़ दिया। 23 फरवरी 1568 ई. की रात्रि में चित्तौड़ का अन्तिम जोहर हुआ तथा दूसरे दिन दुर्गद्वार खोलकर योद्धाओं ने साका किया। इसके साथ ही अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। कुछ समय तक दुर्गम पहाड़ों एवं कुम्भलमेर में रहेगे मुगल महाराणा उदय सिंह ने गोगुन्दा में अपना स्थान कायम किया और वहाँ पर 28 फरवरी, 1572 को उन का देहान्त हुआ। अपनी मृत्यु के कुछ दिवस पूर्व ही महाराणा उदय सिंह ने राजगढ़ी पर प्रताप के औचित्पूर्ण दावे की उपेक्षा कर अपने कनिष्ठ पुत्र जगमाल को युवराज व राज्य का भावी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था किन्तु मेवाड़ के सरदारों के प्रभावी हस्तक्षेप के कारण 28 फरवरी, 1572 को ही प्रताप का मेवाड़ की राजगढ़ी पर राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ। यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से इस तथ्य का द्योतक है कि राजा में देवत्व के निहित होने की अवधारणा के बावजूद सामन्तों में सत्य, न्याय और औचित्य के प्रति निष्ठा थी व गलत राजाज्ञा को अस्वीकार करने का साहस भी था।

प्रताप की गद्दीनशीनी के एक वर्ष पश्चात अप्रैल, 1573 में आमेर के कुंवर मान सिंह कच्छवाह, सितम्बर, 1573 में आमेर के राजा भगवंतदास तथा दिसम्बर, 1573 में राजा टोडरमल अकबर के दूत के रूप में प्रताप से मिले व उन्हें मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करने हेतु सहमत करने का

प्रयास किया किन्तु यह प्रयास निष्फल ही रहा। अन्ततः 18 जून, 1576 को प्रताप व मुगल सेनाओं के बीच हल्दी घाटी का सुप्रसिद्ध युद्ध हुआ जिससे मेवाड़ के प्रमुख योद्धा रामदास मेड़तिरा, रामशाह तंवर, झाला बीदा, झाला मानसिंह, रावत नैतसी इत्यादि वीरता पूर्वक लड़ते हुए काम आए और प्रताप तथा उनके बचे हुए सैनिकों को रणभूमि छोड़नी पड़ी। यद्यपि विजय मुगल सेना की हुई किन्तु वे प्रताप को पकड़ने अथवा उनका मनोबल तोड़ने में असमर्थ रहे। इसके बाद अक्टूबर, 1576 में अकबर ने स्वयम् तथा अक्टूबर, 1577, दिसंबर, 1578 तथा नवंबर 1579 में मुगल सेनापति शहाबाज खां ने लगातार मेवाड़ पर आक्रमण किए किन्तु प्रताप को गिरफ्तार करने अथवा मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार करने में पूर्णतया विफल रहे।

अक्टूबर, 1582 में विजयादशमी के दिन प्रताप ने कुंभलमेर से 40 किमी उत्तरपूर्व में दिवरे गांव के शाही धाने पर आक्रमण किया। मुगल सेना का नेतृत्व सुल्तान खां के हाथ में था। इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई और राजपूत सेना ने मुगलों को अजमेर तक खदेड़ा। दिवरे के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। इसके उपरान्त प्रताप ने गोगुन्दा, कुम्भलगढ़, चण्डा, चावण्ड, गोरगु, मरारिया तथा माण्डलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया।

19 जनवरी, 1597 को अपनी मृत्यु से पूर्व प्रताप ने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर मेवाड़ के लगभग सम्पूर्ण असमानता भी बनी हुई है। ग्लोबल फ़िन्डेक्स 2021 के अनुसार, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास बैंक खाता होने की संभावना 10% कम है। साइबर सुरक्षा एक उभरती चुनौती है। 2023 में डिजिटल धोखाधड़ी से 1.2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ महंगाई भी निम्न और मध्यम आय वर्ग को प्रभावित कर रही है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में दोहरे अंकों की वृद्धि ने महंगाई को 4% के लक्ष्य से ऊपर धकेल रखा है।

पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी भारत की प्रगति को बाधित करती हैं। टिकाऊ विकास लक्ष्यों में भारत 166 देशों में 112वें स्थान पर है। वैश्विक निर्भरता, खास तौर पर चीन से आयात और अमेरिका की विदेश नीति पर निर्भरता, भारत की अर्थिक स्वायत्तता को कमजोर करती हैं। अन्य देशों के साथ तुलना भारत की स्थिति को और स्पष्ट करती है। अमेरिका, 30.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से 30 गुना अधिक है, और 95% वयस्कों के पास बैंक खाता है।

अमेरिका की अर्थव्यवस्था सेवा, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जबकि भारत कृषि और सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। चीन, 19.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अलौपी और वीचेट पे ने चीन में 90% वयस्कों को डिजिटल भुगतान से जोड़ा, लेकिन इसका केंद्रीकृत नियंत्रण भारत के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से अलग है।

जापान और जर्मनी, क्रमशः 4.4 और 4.9 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ, भारत के निकटतम प्रतिस्पर्धी हैं। इनकी प्रति व्यक्ति आय 34,000 और 51,432 डॉलर है। केन्या जैसे विकासशील देश ने एम-पेसा के जरिए वित्तीय समावेशन में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 83% वयस्कों के पास मोबाइल मनी खाता है। भारत की विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विविधता इसे अलग बनाती है, लेकिन बुनियादी ढांचे और साक्षरता में कमी इसे पीछे रखती है। यद्यपि भविष्य की संभावनाएं भारत के लिए आशाजनक हैं। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के

एक-एक प्रतिनिधि की संयुक्त समिति गठित कर साइट का दौरा कर छह सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एनजीटी ने मामले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रमुख पक्षकार मानते हुए प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में तत्काल जोड़ने के भी निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त 2025 को होगी। उल्लेखनीय है कि जाजू ने प्राचीन चिड़ियाघर का अवलोकन कर पुराने विशालकाय पेड़ों एवं विलुप्त होते पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए एनजीटी की शरण ली थी।

भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था : उपलब्धि तो है, लेकिन सफर लम्बा है



राजेन्द्र मोहन शर्मा

भारत की अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसके साथ यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। इस आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय समावेशन रहा है, जिसने समाज के हर वर्ग, खास तौर पर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग को बैंकिंग, ऋण और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं से जोड़ा है। हालांकि, भारत की यह चमकती आर्थिक तस्वीर पूरी तरह सच नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी, संचनान्तरक कमियाँ और सामाजिक चुनौतियाँ इस कहानी को “आधी हकीकत, आधे फसाने” के रूप में देखती हैं।

भारत की आर्थिक प्रगति का आधार 1991 के उदारीकरण सुधारों में निहित है, जिसने वैश्विक व्यापार के दरवाजे खोले। 2015 में भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई, यानी 105% की वृद्धि। यह वैश्विक औसत 3.9% से कहीं अधिक है। 2022 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर पांचवां स्थान हासिल किया और अब जापान को पीछे छोड़ कर अग्रसर है। निर्यात क्षेत्र में भी भारत ने मजबूत प्रदर्शन किया। 2021-22 में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 650 बिलियन डॉलर को पार कर गया, और 2023-24 में इसके 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और व्यावसायिक सेवाओं में भारत की वैश्विक पहचान

बनी है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने विनिर्माण और नव्युत्पाद को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप दर्जनों यूनिकॉर्न कंपनियाँ उभरीं। चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग ने भारत की तकनीकी क्षमता को और मजबूत किया। लेकिन इस आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय समावेशन है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक और समावेशी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। वित्तीय समावेशन का सफर 2005-06 में शुरू हुआ, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) ने इस दिशा में क्रांति ला दी। 2025 तक, 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा हुए। आधार प्रणाली ने 1.3 अरब से अधिक लोगों को डिजिटल पहचान दी, जिससे बैंक खाता खोलना और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आसान हुआ। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने डिजिटल भुगतान को आम जन तक पहुंचाया।

2024 में यूपीआई ने 150 बिलियन से अधिक लेनदेन दर्ज किए, जिनका मूल्य 200 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। यह भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है। मुद्रा योजना ने छोटे और मझोले उद्यमों को 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए, जिसने सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना ने लाखों लोगों को सस्ती बीमा योजनाओं से जोड़ा। विश्व बैंक की 2021 की ग्लोबल फ़िनडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 78% वयस्कों के पास बैंक खाता था, जो 2011 में 35% से कहीं अधिक है। ये उपलब्धियाँ भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने और गरीबी उन्मूलन में योगदान दे रही हैं। हालांकि, आर्थिक प्रगति और वित्तीय समावेशन के दावों में आंकड़ों की बाजीगरी स्पष्ट दिखती है।

भारत की आर्थिक और वित्तीय प्रगति के सामने कई चुनौतियाँ हैं। आय असमानता एक बड़ी समस्या है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण के अनुसार, लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं से तेजी से बढ़ रही है, जो अमीर और गरीब के बीच खाई को दर्शाता है। वित्तीय साक्षरता की कमी भी वित्तीय समावेशन को सीमित करती है। केवल 27% वयस्कों को वित्तीय प्रबंधन की बुनियादी समझ है, जिसके कारण लोग वित्तीय समावेशन में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 83% वयस्कों के पास मोबाइल मनी खाता है। भारत की विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विविधता इसे अलग बनाती है, लेकिन बुनियादी ढांचे और साक्षरता में कमी इसे पीछे रखती है। यद्यपि भविष्य की संभावनाएं भारत के लिए आशाजनक हैं। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के

भारत की आर्थिक और वित्तीय प्रगति के सामने कई चुनौतियाँ हैं। आय असमानता एक बड़ी समस्या है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण के अनुसार, लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं से तेजी से बढ़ रही है, जो अमीर और गरीब के बीच खाई को दर्शाता है। वित्तीय साक्षरता की कमी भी वित्तीय समावेशन को सीमित करती है। केवल 27% वयस्कों को वित्तीय प्रबंधन की बुनियादी समझ है, जिसके कारण लोग वित्तीय समावेशन में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 83% वयस्कों के पास मोबाइल मनी खाता है। भारत की विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विविधता इसे अलग बनाती है, लेकिन बुनियादी ढांचे और साक्षरता में कमी इसे पीछे रखती है। यद्यपि भविष्य की संभावनाएं भारत के लिए आशाजनक हैं। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के

भारत की आर्थिक और वित्तीय प्रगति के सामने कई चुनौतियाँ हैं। आय असमानता एक बड़ी समस्या है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण के अनुसार, लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं से तेजी से बढ़ रही है, जो अमीर और गरीब के बीच खाई को दर्शाता है। वित्तीय साक्षरता की कमी भी वित्तीय समावेशन को सीमित करती है। केवल 27% वयस्कों को वित्तीय प्रबंधन की बुनियादी समझ है, जिसके कारण लोग वित्तीय समावेशन में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 83% वयस्कों के पास मोबाइल मनी खाता है। भारत की विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विविधता इसे अलग बनाती है, लेकिन बुनियादी ढांचे और साक्षरता में कमी इसे पीछे रखती है। यद्यपि भविष्य की संभावनाएं भारत के लिए आशाजनक हैं। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के

भारत की आर्थिक और वित्तीय प्रगति के सामने कई चुनौतियाँ हैं। आय असमानता एक बड़ी समस्या है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण के अनुसार, लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं से तेजी से बढ़ रही है, जो अमीर और गरीब के बीच खाई को दर्शाता है। वित्तीय साक्षरता की कमी भी वित्तीय समावेशन को सीमित करती है। केवल 27% वयस्कों को वित्तीय प्रबंधन की बुनियादी समझ है, जिसके कारण लोग वित्तीय समावेशन में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 83% वयस्कों के पास मोबाइल मनी खाता है। भारत की विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विविधता इसे अलग बनाती है, लेकिन बुनियादी ढांचे और साक्षरता में कमी इसे पीछे रखती है। यद्यपि भविष्य की संभावनाएं भारत के लिए आशाजनक हैं। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के

भारत की आर्थिक और वित्तीय प्रगति के सामने कई चुनौतियाँ हैं। आय असमानता एक बड़ी समस्या है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण के अनुसार, लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं से तेजी से बढ़ रही है, जो अमीर और गरीब के बीच खाई को दर्शाता है। वित्तीय साक्षरता की कमी भी वित्तीय समावेशन को सीमित करती है। केवल 27% वयस्कों को वित्तीय प्रबंधन की बुनियादी समझ है, जिसके कारण लोग वित्तीय समावेशन में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 83% वयस्कों के पास मोबाइल मनी खाता है। भारत की विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विविधता इसे अलग बनाती है, लेकिन बुनियादी ढांचे और साक्षरता में कमी इसे पीछे रखती है। यद्यपि भविष्य की संभावनाएं भारत के लिए आशाजनक हैं। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के

भारत की आर्थिक और वित्तीय प्रगति के सामने कई चुनौतियाँ हैं। आय असमानता एक बड़ी समस्या है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण के अनुसार, लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं से तेजी से बढ़ रही है, जो अमीर और गरीब के बीच खाई को दर्शाता है। वित्तीय साक्षरता की कमी भी वित्तीय समावेशन को सीमित करती है। केवल 27% वयस्कों को वित्तीय प्रबंधन की बुनियादी समझ है, जिसके कारण लोग वित्तीय समावेशन में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 83% वयस्कों के पास मोबाइल मनी खाता है। भारत की विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विविधता इसे अलग बनाती है, लेकिन बुनियादी ढांचे और साक्षरता में कमी इसे पीछे रखती है। यद्यपि भविष्य की संभावनाएं भारत के लिए आशाजनक हैं। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के

भारत की आर्थिक और वित्तीय प्रगति के सामने कई चुनौतियाँ हैं। आय असमानता एक बड़ी समस्या है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण के अनुसार, लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं से तेजी से बढ़ रही है, जो अमीर और गरीब के बीच खाई को दर्शाता है। वित्तीय साक्षरता की कमी

हम महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का कर रहे काम : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्यागकर जंगलों का कष्टमय जीवन जीया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप महान योद्धा, परम स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उन्होंने हमें सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्रह्त्त के मार्ग पर चलना सिखाया। शर्मा बुधवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'शौर्य गाथा के रंग' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा ने राजस्थान की महान धरती पर जन्म लिया। उनका सम्पूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणापुंज है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता से देश-दुनिया के ख्यातमान इतिहासकार भी प्रभावित हुए। कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा करते हुए हल्दीघाटी के युद्ध को धर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैरथान बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी देशभक्ति,



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'शौर्य गाथा के रंग' कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

वीरता एवं शौर्य को काल और भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है।

शर्मा ने कहा कि हम महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड-ह-हल्दी घाटी-गो गुं दा-

कुंभलगढ़-दिवेर-उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप ट्रस्टि सर्किट विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें संप्रभुता और

स्वतंत्रता की रक्षा करना सिखाता है। उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात कर भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में मजबूत शक्ति के रूप में पहचान बनाई है। इस शक्ति की एक झलक पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी। इस ऑपरेशन के माध्यम से पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वालों की मिट्टी में

राज्य सरकार बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित : अविनाश गहलोत

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र की नींव हैं, जिस पर वर्तमान खड़ा है और भविष्य निर्मित होगा। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां बुजुर्गों को न केवल सहारा मिले, बल्कि वे स्वयं को समाज

- ‘वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र की नींव हैं, जिस पर वर्तमान खड़ा है और भविष्य निर्मित होगा’
- विभिन्न सेशंस में बुजुर्गों को मनोवैज्ञानिक, योग प्रशिक्षक, आहार विशेषज्ञ, सायबर एवं पुलिस अधिकारियों ने दिए विभिन्न पहलुओं पर परामर्श



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बुधवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं सशक्तिकरण पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया।

गृह, स्वयंसिद्धा आश्रम, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड तथा अटल वयो अभ्युदय योजना सरीखी विभिन्न योजनाएं संचालित कर हजारों वरिष्ठजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि इन सबके अलावा प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देवस्थान विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह ताकत और उत्तरजीविशा है, सभी प्रकार के उतार-चढ़ाव और निराशाओं, परीक्षाओं

और बीमारियों पर विजय है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राकों ने कहा कि विभाग द्वारा वरिष्ठजनों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज में हो रहे विभिन्न बदलावों के चलते बुजुर्गों में एकाकीपन और अकेलापन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी दशा से बचाव के लिए बुजुर्ग आर्थोपार्जन के साथ स्वयं को व्यस्त रखें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें।

कार्यशाला में नामचीन मनोवैज्ञानिक, श्रेष्ठ योग प्रशिक्षक, बेहतरीन आहार विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्था, पुलिस, सायबर सेल के अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने योग व ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य और निवारक

देखभाल सत्र, पोषण व स्वास्थ्य रूप में वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में जागरूकता, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम और प्रतिक्रिया, सामाजिक-जुड़ाव और समय प्रबंधन के लिए रणनीतियां, वित्तीय योजना और डिजिटल साक्षरता और अंतर पीढ़ीगत संश्लेष के जरिए वृद्धजनों को जागरूक किया।

इस अवसर पर निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक केसर लाल मीणा, अतिरिक्त निदेशक रीना शर्मा, संयुक्त निदेशक बीपी चंदेल, जोनल हेड आईसीआईसीआई विकास माथुर, यूएनसीपीयू के दिव्यांश गुला सहित कई विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

सावरकर जयंती पर मदन राठौड़ ने पुष्पांजलि अर्पित की

जयपुर। स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में भाजपा जिला कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और वीर सावरकर के स्वदेश प्रेम, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रसेवा के सिद्धांतों से प्रेरित होकर युवाओं से राष्ट्र निर्माण के प्रति भागीदारी का आह्वान किया। राठौड़ ने कहा कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर का जीवन राष्ट्र के लिए संघर्ष, विचार और त्याग का प्रतीक रहा है। उनके आदर्शों को जन्मानुसार कर पहुंचाने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। सावरकर ने जहाँ एक ओर स्वदेशी आंदोलन को आत्मसात किया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सुधार, शिक्षा और आधुनिक भारत की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्षारोपण केवल प्रकृति से प्रेम नहीं, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदारी है। वीर सावरकर ने हमें सिखाया कि राष्ट्रसेवा के मार्ग पर विचार, कर्म और साहस तीनों का संतुलन आवश्यक है। आज हम एक हरित और समृद्ध भारत के संकल्प के साथ पौधारोपण कर रहे हैं। राठौड़ ने हरियाली के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का संदेश देते हुए कहा कि भाजपा उदयपुर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण का यह आयोजन केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं है ,बल्कि यह एक सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन का हिस्सा है।

जयपुर। रालसा के तत्वावधान में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय रीटा तेजपाल (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय) की अध्यक्षता में नालसा द्वारा जारी स्क्रीम जागृति एवं डॉन के ऑरिएंटेशन सेशन का आयोजन किया गया। साथ ही आशा- बाल विवाह की रोकथाम की संचालन प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में बाल विवाह रोकथाम तथा बाल विवाह हो जाने पर पीडित बालक-बालिका के पुनर्वास संबंधी विषयों पर तथा जमीनी स्तर पर आम व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक योजना के बारे में जानकारी हो इस संबंध में विभागों से समन्वय कर आम जन को सरकार योजनाओं का प्रचार प्रसार पैरा लीगल कॉर्लेंटियस के माध्यम से करवाने के संबंध में संकल्प लिया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर मेट्रो द्वितीय की सचिव (अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश) पल्लवी शर्मा ने बताया कि सेशन के दौरान दिए गए प्रशिक्षण में ड्रग्स न लेने के संबंध में तथा उसके कुप्रभावों की जानकारी देने के संबंध में विद्यालयों, कारागृह, गली मौहल्लों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करवाना तय



रालसा के तत्वावधान में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय रीटा तेजपाल (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय) की अध्यक्षता में नालसा द्वारा जारी स्क्रीम जागृति एवं डॉन के ऑरिएंटेशन सेशन का आयोजन किया गया।

किया गया तथा ड्रग एडिक्ट की पहचान कर उसे नशा मुक्ति केन्द्र में भिजवाए जाने की व्यवस्था करने और उसे समुचित रूप से पुनर्वासित करने के संबंध में कदम उठाने हेतु चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिता मुवाल सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर, मनमोहन नगर निगम हैरिटेज

जयपुर, मुकुट सिंह उपायुक्त, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, विजय शर्मा डीसीपीयू जयपुर, जनार्दन कुमार आत्रेय चीफ एलएण्डसीएस जयपुर महानगर द्वितीय, शिवरत्न गोदारा, एसपी शास्त्री नगर, जयपुर, पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम, रामनिवास शर्मा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर, सुनील कुमार सिंघल जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर, सुरेश महारानिया अतिरिक्त पुलिस

नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्समीमांकन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा



मंत्रीमण्डलीय उप समिति के सदस्य जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत, राज्यमंत्री वन विभाग संजय शर्मा, राज्यमंत्री सहकारिता विभाग गौतम कुमार तथा समिति के संयोजक राज्यमंत्री नगरीय विकास विभाग झाबर सिंह खरॉ ने बैठक में जोधपुर, भरतपुर एवं जयपुर संभाग की नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्समीमांकन के प्रस्तावों पर समीक्षा एवं विचार विमर्श किया गया।

जयपुर। मंत्रीमण्डल सचिवालय के आदेशों की अनुपालना में बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में नगरीय प्रशासन की और अधिक प्रभावशाली, उत्तरदायी एवं समावेशी बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण द्वितीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्समीमांकन से जुड़े प्रस्तावों पर गहन परीक्षण और विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मंत्रीमण्डलीय उप समिति के सदस्य जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत, राज्यमंत्री वन विभाग संजय शर्मा, राज्यमंत्री सहकारिता

विभाग गौतम कुमार तथा समिति के संयोजक राज्यमंत्री नगरीय विकास विभाग झाबर सिंह खरॉ द्वारा इस बैठक में जोधपुर, भरतपुर एवं जयपुर संभाग की नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्समीमांकन के प्रस्तावों पर समीक्षा एवं विचार विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रारम्भ की गई इस पहल का मूल उद्देश्य राज्य के नगरीय निकायों को वर्तमान यथार्थ और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है, ताकि आमजन तक प्रशासन की पहुँच सुलभ हो, स्थानीय विकास को गति मिले

और शहरी क्षेत्रों में जीवनस्तर में सार्थक सुधार आए। यह प्रक्रिया न केवल नगरीय प्रशासन को अधिक संगठित और जनोन्मुखी बनाएगी, बल्कि स्थानीय शासन में पारदर्शिता, समावेशिता और उत्तरदायित्व की भावना को भी सुदृढ़ करेगी। यह निर्णय प्रक्रिया राजस्थान और शहरी सुशासन की दिशा में एक नई ऊँचाई तक पहुँचाने की और सशक्त कदम है। इस बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, निदेशक एवं विशेष सचिव इन्द्रजीत सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे।

समरावता उपद्रव प्रकरण में नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई टली

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने समरावता में हुए उपद्रव के मामले में आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 मई तक टाल दी है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान नरेश मीणा की

ओर से अधिवक्ता महेश शर्मा ने कहा कि एसटी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि घटना में पुलिस ने ज्यादाती की है। पुलिस ने लोगों को मौके पर जमा होने दिया और बाद में उन पर कार्रवाई कर दी। वहीं आयोग की सिफारिश पर प्रशासन ने पीड़ितों को मुआवजा भी दिया है। प्रकरण में याचिकाकर्ता पर हिंसा का आरोप नहीं है। वहीं जिन अन्य

लोगों पर हिंसा का आरोप है, उनमें से कई जमानत पर रिहा हो चुके हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले में गत 11 फरवरी को आरोप पत्र पेश हो चुका है और अदालत ने 14 फरवरी को उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं अब तक निचली अदालत में ट्रायल आरंभ होकर उस पर चार्ज नहीं लगे हैं। ऐसे में उसे

जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया की एफआईआर और आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर स्पष्ट आरोप हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में और तथ्य पेश करने की गुहार करते हुए सुनवाई टालने की गुहार की। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 30 मई को रखी है।

पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर टली सुनवाई

जयपुर। ईडी मामले की विशेष कोर्ट में बुधवार को जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़े ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत अर्जी पर बहस शनिवार तक टल गई। ईडी की ओर से मामले में बहस के लिए समय मांगा गया। जिस पर कोर्ट ने उसे समय दे दिया। इससे पहले मंगलवार

को महेश जोशी की ओर से बहस में कहा कि उसे केस में झूठा फंसाया गया है। एसबी की एफआईआर और मामले में पेश चालान में उसका नाम नहीं है। ईडी ने मार्च, 2024 में उसे समन दिया था। जिसका जवाब ईडी को भेजा गया था। इसके बाद ईडी ने करीब एक साल तक कोई कार्रवाई नहीं की और पिछले दिनों उसे अचानक बुलाकर गिरफ्तार

कर लिया। इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में जिन 50 लाख रुपए का हवाला दिया है, वह जुलाई, 2023 में उसके बेटे की कंपनी ने लोन के रूप में लिया था और उसे लौटाया जा चुका है। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की पहले ही जमानत हो चुकी है। उससे कोई रिकवरी नहीं हुई है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए

भिनाय में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पित है। औद्योगिक निवेश से स्थानीय रोजगार बढ़ाने के साथ विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए अजमेर की भिनाय तहसील स्थित ग्राम कर्नईकला में 106 हैक्टेयर से अधिक भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 92 के तहत भूमि गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आवंटित की गई है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। एक अन्य निर्णय के तहत मुख्यमंत्री शर्मा ने बारां जिले की अंता तहसील के ग्राम सोरसन में 765 केवी जीएसएस के लिए भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 39.17 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को कीमतन आवंटित किया गया है। इसकी स्थापना से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी।

कार्रवाई से पूर्व सुनवाई का मौका देना है प्राधिकारी की बाध्यकारी ड्यूटी : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने या आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का मौका देना संबंधित प्राधिकारी की बाध्यकारी ड्यूटी है और वह इससे इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ ही अदालत ने विद्यार्थी के नकल से जुड़े इस मामले में एनटीए और जेईई परीक्षा आयोग को कहा है कि वह याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर नए सिरे से आदेश पारित करें। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह एक सप्ताह में संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पेश हो और प्राधिकारी उसका पक्ष सुनकर दो सप्ताह में नया आदेश जारी करें। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश माहिर बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामले में

याचिकाकर्ता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। वहीं उस पर लगाया गया दंड उसके करियर को बर्बाद कर देगा और आने वाले समय में यह कर्लक के संकेत साध रहेगा। इसके साथ ही उसे रोजगार पाने में भी बाधा उत्पन्न होगी। याचिका में अधिवक्ता दीपक बिश्नोई ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जेईई मेंस, 2025 की परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने का बतारक उसका परिणाम रोक लिया गया। वहीं उसे आगामी दो सत्रों की परीक्षा देने के लिए अपात्र घोषित कर दिया। याचिका में कहा गया कि परीक्षा कक्ष के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जबकि संबंधित प्राधिकारी ही इस साक्ष्य को लेकर स्पष्ट नहीं है। वहीं कार्रवाई से पहले न तो उसे

नोटिस दिया गया और ना ही उसे सुनवाई का मौका मिला। जबकि नियमानुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल फैसला देने से पहले उसे सुना जाना जरूरी है। दूसरी ओर एनटीए और परीक्षा आयोग की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता परीक्षा के दौरान पास बैठे दूसरे अभ्यर्थी की कॉपी से नकल कर रहा था। दोनों अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका में उत्तर शब्दशः लिखे गए थे। यह सब सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे में उसे अनुचित साधन का उपयोग करने का आरोप मानते हुए अगले दो सत्रों की परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित प्राधिकारी को मामले में याचिकाकर्ता को सुनकर नए सिरे से आदेश देने को कहा है।



The diagram illustrates the decomposition of the tensor product of two representations. On the left, there are two rows of four dots each, representing the tensor product of two representations. The top row has two dark grey dots followed by two light grey dots. The bottom row has two dark grey dots followed by two black dots. An arrow points from this tensor product to a direct sum symbol ($\oplus$). To the right of the symbol is another set of two rows of four dots each. The top row has two dark grey dots followed by two light grey dots, and the bottom row has two dark grey dots followed by two black dots. This represents the direct sum of two representations.

